संभाव्यता को ध्यान में रखती है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित दर की दुकानें इस तरह से खोलने की सलाह दी है कि उपभोक्ता उन तक आसानी से पहुंच सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दुकान का मापदण्ड सुझाया गया था। दुर्गम क्षेत्रों तथा आबादी के घनत्व में अंतर को देखते हुए इस संबंध में अपवाद हो सकते हैं।

दिल्ली में राशन कार्ड

3261. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली प्रशासन को राशन कार्ड जारी करने के लिए क्षेत्र-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं; और

(ग) शेष राशन कार्ड कब तक जारी कर दिए जाने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी गई है :—

	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	रद्द किए गए आवेदनों की संख्या	जारी किए गए खाद्य कार्ड	लम्बित आवेदन
1. दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम व नई दिल्ली	29894	2335	26869	690
2. (उत्तर, उत्तर-पूर्व व केन्द्रीय	16717	1544	14014	1159
3. उत्तर पश्चिम, पूर्व व पश्चिम	38892	3481	35411	—

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि बकाया आवेदनों के सत्यापन तथा शीघ्र निपटान के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा कार्य की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से परिवीक्षा की जाती है।

ISO-9000 certification for corporate bodies

3262. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a number of corporate bodies are now keen to secure ISO-9000 certification of quality for exportable goods;

(b) whether Government propose to assign the said scheme to Bureau of Indian Standards; and